

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, सिरौही (राज.)

बईजलास श्री सुरेन्द्र कुमार सोलंकी, आई.ए.एस.

प्रार्थना-पत्र संख्या 13/2019

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थीगण
प्राधिकृत अधिकारी आदर्श कॉ.ऑ. बैंक लि. सिरौही।		1. मै. शिवम् इंटरनेशनल प्रो. श्री अशोक कुमार पुत्र श्री गोपाल रावल निवासी 4005 राधाकृष्ण लोजिरिटिक पार्क भारत केंसर हॉस्पिटल के पास काडोरा मेन रोड सरौली सूरत 395010 गुजरात।

प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 14 दी सिक्युराइजेशन एण्ड रिकन्सट्रक्शन ऑफ फाईनेन्शियल

एस्सेट्स एण्ड एन्फोर्समेन्ट ऑफ सिक्युरिटी इन्ट्रेस्ट एक्ट 2002

उपरिथिति :-

1. श्री चंदन सिंह डाबी अधिवक्ता प्रार्थी बैंक ।
2. श्री गजेन्द्र सिंह देवडा अधिवक्ता अप्रार्थी ।

निर्णय

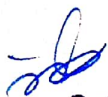
दिनांक : 20.9.2019

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 दी सिक्युराइजेशन एण्ड रिकन्सट्रक्शन ऑफ फाईनेन्शियल एस्सेट्स एण्ड एन्फोर्समेन्ट ऑफ सिक्युरिटी इन्ट्रेस्ट एक्ट 2002 के तहत अप्रार्थीगण के विरुद्ध प्रस्तुत किया । प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया ।

प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी पक्ष के द्वारा अप्रार्थी श्री अशोक कुमार पुत्र श्री गोपाल रावल को राशि रूपये 80,000,00/- की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई तथा पुनर्भुगतान हेतु अप्रार्थी ने अपनी जायदाद बैंक के पास बतौर अमानत बंधक रखी थी । अप्रार्थी ने अपनी निम्न जायदाद को बैंक/कम्पनी के पक्ष में रहन कर दिया। प्रथम श्री अशोक कुमार पुत्र श्री गोपाल रावल के नाम साम्यिक बंधक भूमि एवं निर्माण पट्टा नम्बर 166 असावा तहसील रेवदर जिला सिरौही जिसका कुल क्षेत्रफल 4212 वर्ग फिट हैं। एवं द्वितीय श्री हिराराम पुत्र श्री खुबाराम माली के नाम साम्यिक बंधक भूमि एवं निर्माण पट्टा नम्बर 294 सिरौडी तहसील रेवदर जिला सिरौही जिसका कुल क्षेत्रफल 3600 फिट हैं।

अप्रार्थी द्वारा नियमित रूप से प्रार्थी के बैंक/कम्पनी को ऋण का भुगतान करने में असफल रहने पर प्रार्थी द्वारा ऋण राशि मय ब्याज के अदा करने हेतु उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी के नाम रजिस्टर्ड नोटिस दिनांक 25.2.2019 को जारी किये गये ।




जिला मजिस्ट्रेट, सिरौही

जो पंजीकृत डाक के माध्यम से तामिल करवाये गये उसके पश्चात भी अप्रार्थी द्वारा ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नही करने पर प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थीयो के द्वारा बतोर जमानत रहन रखी गई सम्पति इत्यादि का कब्जा प्रार्थी बैंक/कम्पनी को संभलाने हेतु यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया ।

प्रार्थी के लायक अधिकारी/अधिवक्ता की बहस सुनी । विद्वान अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र मे वर्णित बिन्दुओ की पुष्टि करते हुए कहा कि प्रार्थी बैंक/कम्पनी एक नियमित निकाय है जो अपनी शाखाओं के माध्यम से ऋण देने का व्यवसाय करती है उसकी शाखाओं मे से एक सिरौही मे भी स्थित व कार्यरत है । प्रार्थी बैंक/संस्था द्वारा अप्रार्थीगण को रूपये 80,00,000/- ऋण स्वीकृत किया था । जिसकी एवज में अपनी जायदाद बैंक/कम्पनी के पक्ष में बन्धक रखी गई थी जिसका वर्णन प्रार्थना पत्र मे किया गया है । बहस मे कहा कि अप्रार्थी द्वारा प्रार्थी पक्ष को नियमित रूप से ऋण राशि व ब्याज राशि का भुगतान नही करने के कारण एक्ट की धारा 13(2) के अन्तर्गत नोटिस जारी किये गये किन्तु अप्रार्थी द्वारा देय ऋण राशि का भुगतान नही किया गया । भुगतान नही करने के फलस्वरूप अप्रार्थी स्वयं जिम्मेदार है । अतः अप्रार्थीगण द्वारा बतोर जमानत प्रार्थी बैंक/कम्पनी के पक्ष मे रहन रखी गई उक्त जायदाद इत्यादि का कब्जा प्रार्थी बैंक/कम्पनी को दिलाया जावे ।

दोनो पक्षों की बहस सुनी । अप्रार्थी द्वारा राशि रूपये 80,00,000/- का ऋण लिया था । ऋण राशि के बदले में अप्रार्थी द्वारा अपनी जायदाद को बैंक/कम्पनी के पक्ष मे उक्त जायदाद रहन रखी है । प्रार्थी द्वारा नियमानुसार धारा 13(2) के अधीन अप्रार्थी को रजिस्टर्ड नोटिस भी दिनांक 25.2.2019 को जारी किये है जिनकी प्राप्ति के पश्चात् भी अप्रार्थी द्वारा देय राशि का भुगतान नही किया है ।

दी सिक्युराइडेशन एण्ड रिकन्सट्रक्शन ऑफ फाईनेन्शियल एस्सेट्स एण्ड एन्फोर्समेन्ट आफ सिक्युरिटी इन्ट्रेस्ट एक्ट 2002 की धारा 14 निम्न प्रकार है :-

14 . Chief Metropolitan Magistrate or District Magistrate to assist secured creditor in taking possession of secured asset – (1) Where the possession of any secured assets is required to be taken by the secured creditor or if any of the secured assets is required to be sold are transferred by the secured creditor under the provisions of this Act, the secured creditor may, for the purpose of taking possession or control of any such secured asset, request, in writing the Chief Metropolitan Magistrate or the District Magistrate within whose jurisdiction any such secured asset or other document, relating thereto may be situated or found to take possession thereof and the



[Handwritten signature]
जिला मजिस्ट्रेट, जहानपुर

Chief Metropolitan Magistrate or as the case may be, the District Magistrate shall, on such request being made to him –

- (a) take possession of such asset and documents relating thereto and
(b) forward such assets and documents to the secured creditor

(2) For the purpose of securing compliance with the provisions of sub-section (1), the Chief Metropolitan Magistrate or the District Magistrate may be take or cause to be taken such steps and use, or cause to be used, such force, as may, in his opinion, be necessary.

परिणामस्वरूप तथ्यों के संदर्भ में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 दी सिक्कुराइटेशन एण्ड रिकन्सट्रक्शन ऑफ फाईनेन्शियल एस्सेट्स एण्ड एन्फोर्समेन्ट आफ सिक्कुरिटी इन्ट्रेस्ट एक्ट 2002 में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी द्वारा प्रार्थी बैंक/कम्पनी के पक्ष में प्रतिभूति के रूप में रखी गई जायदाद श्री अशोक कुमार पुत्र श्री गोपाल रावल के नाम साम्यिक बंधक भूमि एवं निर्माण पट्टा नम्बर 166 असावा तहसील रेवदर जिला सिरोही जिसका कुल क्षेत्रफल 4212 वर्ग फिट हैं। एवं द्वितीय श्री हिराराम पुत्र श्री खुबाराम माली के नाम साम्यिक बंधक भूमि एवं निर्माण पट्टा नम्बर 294 सिरोडी तहसील रेवदर जिला सिरोही जिसका कुल क्षेत्रफल 3600 फिट हैं।

जिसका अडोस पडोस निम्न प्रकार है।

प्रथम :- पूर्व- घर व चमनाराम भील की जमीन।

पश्चिम- गली।

उत्तर- रास्ता।

दक्षिण- घर व नगाजी धुलाजी भील का बाड़ा।

द्वितीय :- पूर्व- रास्ता व दरवाजा।


पश्चिम- गली।

उत्तर- गली व विद्यालय भूमि।

दक्षिण- लल्लूराम रावल का मकान।

उपरोक्त जायदाद का कब्जा अप्रार्थी से प्राप्त कर जरिये संबंधित पुलिस थाना से प्रार्थी बैंक/कम्पनी को संभलाये जाने का आदेश दिया जाता है यदि उक्त सम्पति किसी भी तरीके से बंद पायी जाती है तो ताला तोड़कर उक्त सम्पति पर प्रार्थी बैंक अपना कब्जा स्थापित करें। आदेश की प्रति वास्ते पालनार्थ पुलिस अधीक्षक सिरोही, संबंधित थानाधिकारी पुलिस थाना एवं प्रार्थी बैंक/कम्पनी को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जायेगा। आदेश आज दिनांक 20.9.2019 को सरे ईजलास सुनाया गया।




(सुरेन्द्र कुमार सोलंकी)
जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही